(b) Does not arise.

Villages under deep poverty

533. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state that the number of villages under deep poverty in the country, State-wise, and the number of the families residing in those villages?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION) (SHRI VILAS MUTTEMWAR): According to Planning Commission, estimates of incidence of poverty are prepared at the State level and no estimates of incidence of poverty are made at the village level. Hence the estimates of the number of villages under deep poverty as also the number of families residing in the villages are not available.

Misuse of Government Transport by CPWD Officials

534. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government transport is being used by officers below the rank of Chief Engineers in the CPWD for coming and going to their offices from their residences;

(b) if so, the reasons for not checking the misuse of Government vehicles; and

(c) the steps taken to curb the misuse on priority basis?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI R.K. DHAWAN): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Proposal to set up industries in Orissa during Eighth Plan period

535. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of major and medium industries proposed to be set up in Orissa during Eighth Plan;

(b) the break-up of those proposed projects public sector, private sector and joint sector-wise; and

(c) the places identified for the establishment of those units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA): (a) to (c) No targets for setting up industries during 8th Five Year Plan for Orissa have been fixed. Most of the industries are delicenced and during 8th Five Year Plan period (April 1992 to October, 1995) 116 Industrial Entrepreneurs Memoranda have been filed for delicenced sector for locating industries in Orissa. For licensable sector, a total number of six Letters of Intent have been granted under the Provisions of Industries (Development & Regulation) Act during the same period for setting up various industries in Orissa. Out of these one Letter of Intent has been granted for Central Public Sector and the rest are for private sector. The locations are in Ganjam, Paradeep, Jujpur and Balasore districts.

पंजाब में लघु उद्योगों के विकास हेतु कार्य-योजना

536. **श्री इकबाल सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए पंजाब में लघु उद्योगों का विकास करने, उन्हें सुदृढ़ बनाने और उन्हें पूर्ण सरकारी संरक्षण देने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान लघु क्षेत्र में अनुमानतः कितनी पूंजी का निवेश किया जायेगा तथा पिछले वित्तीय

वर्ष में किये गये निवेश की तुलना में यह निवेश कितना अधिक है और इस अवधि के दौरान रोज़गार के कितने अतिरिक्त अवसरों के सृजित होने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग विभाग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) लघु उद्योगों का संवर्धन और विकास करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रोत्साहन उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है जो नीतियों के निर्धारण और विभिन्न अभिकरणों की गतिविधियों का समन्वय करने के अतिरिक्त है। भारत सरकार के प्रोत्साहन उपायों को कार्यान्वयन देश में लघु उद्योग विकास संगठन के माध्यम से किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो देश में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए बनाई गयी हैं इस प्रकार हैं—औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, उत्पाद-सह-प्रक्रिया विकास केन्द्र, उद्यमीयता विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रबन्ध प्रशिक्षण, निर्यात संवर्धन, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, एकीकृत अवसंरचना विकास योजना, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि। इन योजनाओं के लाभ भी पंजाब में लघु उद्योगों को प्राप्त हैं।

पंजाब में विशेष करके परिचालित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं ये हैं— हस्त-औजार संस्थान, जालंधर, केन्द्रीय औजार कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र, लुधियाना; एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र, टांडा, जिला होशियारपुर; तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना। लघु उद्योग सेवा संस्थान, लुधियाना तकनीकी आर्थिक परामर्शदायी सेवाएं मुहैया करता है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में पंजाब राज्य के लिए अनुमोदित योजनागत परिव्यय राशि ग्रा०ल०उ० क्षेत्र के लिए 16 करोड़ रुपया है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत, वर्ष 1995-96 में पंजाब के लिए 15,000 लाभ-भोगियों का लक्ष्य आबंटित किया गया है। लाभग्राहियों को सब्सिडी राशि बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। केन्द्र सरकार ने इन कार्यान्वयनकारी बैंकों को धन राशि जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत किया है। पंजाब को प्रशिक्षण कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिए 74.34 लाख रुपये की धनराशि 13.11.95 को जारी की गई है जबकि वर्ष 1994-95 में प्रशिक्षण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए 62.40 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई थी। 1995-96 में हस्त औजार संस्थान, जालंधर और केन्द्रीय औजार कक्ष, लुधियाना के लिए क्रमशः 40 लाख रु० और 60 लाख रु० का प्रावधान किया गया है जबकि 1994-95 में 40 लाख रु० और 55 लाख रु० का प्रावधान था।

(ग) सरकार लघु औद्योगिक इकाइयों में पूंजी निवेश नही करती है। लघु क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों में पूंजी निवेश करना उन उद्यमियों का काम है जो वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता लेते हैं।

Construction of Government Accommodation

537. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the steps taken to sanction adequate funds to tide-over the housing needs of the Government servants;

(b) the number of quarters constructed pool-wise in the last five years, city-wise and type-wise;

(c) the number of quarters, type-wise and city-wise, proposed/cleared for construction during 1995, 1996 and 1997;

(d) whether the Supreme Court had directed Government in their order dated 17th July, 1995 to provide residential accommodation to all its employees within five years of service; and

(e) if so, the details of action taken thereon/reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI R.K. DHAWAN): (a) Funds for Central Plan Schemes, including the Scheme for construction of General Pool residential accommodation, are allocated based on the availability of resources and the relative inter-se priorities of various schemes. The expenditure incurred during the three years of the 8th Plan from 1992-93 to 1994-95 on construction of General Pool accommodation was Rs. 82.82 crores. The allocation for